



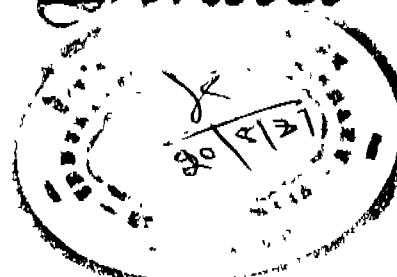
भारत का गज़त

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—कांड 1
PART I—Section 1

प्रधानमंत्री से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 132]

नई वित्ती पारदार, जून 22, 1987/अषाढ़ 1, 1909

No. 132]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 1987/ASADHA 1, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ दर्शन की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय			1	2	3	4
भारत व्यापार विवरण						
सार्वजनिक सूचना सं. 192 भारतीय (पी एन) /85—88						
मई दिवंगी, 22 जून, 1987						
विवरण: अप्रैल, 1985—मार्च 1988 के लिए आयात एवं नियांत्रिति।						
का. सं. 9/27/87-ई पी एन.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 1-आई टी सी (पी एन) /85—88, विनाक 12 अप्रैल, 1985 के अधीन प्रकाशित यथासंबोधित आयात एवं नियांत्रिति अप्रैल 1985—मार्च, 1988 की ओर द्याव दिलाया जाता है।						
2. नीति में निम्नलिखित संशोधन दीवाने तिविष्ट उपर्युक्त स्थानों पर किए जाएँगे:—						

क्रम	आयात एवं	संदर्भ	संशोधन
सं.	नियांत्रिति		
	विवरण		
	1985-88		
	विवरण		
	पृष्ठ सं		

(1) (2) (3) (4)

(1) 290 परिविष्ट-19 इस उपर्युक्त को नियांत्रित द्वारा प्रतिलिपि-उपर्युक्त (2) पिछे किया जाएगा:—

(2) ऐसे नियमित नियांत्रितों के मामले में जिनमा लोन वर्ती का भारतीय नियांत्रित विवाद है वहाँ लोनवर्ती लोइरें अधिकारी नियांत्रित आयात को बढ़ाव के लिए ऐसी प्रशंसित के लिए एक दूसरे के पायार पर विवाद कर सकती है।

ऐसे मामलों में, लोनवर्ती अधिकारी लाइसेंसिंग समितियों द्वारा नियांत्रित के लिए और आगे बढ़ाव दे सकती है। नियांत्रित आयात प्रशंसित में बढ़ाव करने के लिए अन्य नियांत्रितों के आधेनर्नों के मामले में केवल लोनवर्ती अधिकारी लाइसेंस समितियों द्वारा केवल 6 महीने की प्रशंसित के लिए विवाद किया जा सकता है। समाव्ययत: इस प्रशंसित के बाद नियांत्रित आयात के लिए और कोई आगे बढ़ाव नहीं दी जाएगी। तथापि, विवेष मामलों में मुख्य नियंत्रक, अ.प. ए.नी.ट. के कार्यालय में अधिकारी लाइसेंस समिति नियांत्रित आयात प्रशंसित में और आगे बढ़ाव देने के लिए प्रत्येक ऐसे मामले के दूसरे द्वारा द्याव द्याव के लिए रखकर विचार कर सकती है। नियांत्रित उत्पाद केसेट (बोदियो या विडियो) के मामले में, किसी भी प्राधिकारी द्वारा किसी भी स्थित के प्रधीन नियांत्रित आयात के लिए कोई भी बढ़ाव नहीं दी जाएगी।

3. उपर्युक्त संशोधन लोकहित में किए गए हैं।

राजीव लोकहित मिशन,
मुख्य नियंत्रक, आयात एवं नियांत्रित
मंजुला सुवाहमणियम, संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात एवं नियांत्रित

MINISTRY OF COMMERCE

(1) (2) (3) (4)

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 192-ITC(PN)/85-88

New Delhi, the 22nd June, 1987

Subject:-Import & Export Policy for April 1985—March 1988.

F. No. 9/27/87-EPC:— Attention is invited to the Import & Export Policy for April 1985—March 1988, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1-ITC (PN)/85-88 dated the 12th April 1985 as amended.

2. The following amendments shall be made in the policy at appropriate places indicated below:—

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments		
			(1)	(2)	(3)
(1)	290	Appendix-19	This sub-para shall be substituted by the following:— "(2) In the case of regular exporters having three years past export performance, the Regional Licensing Authorities may consider, on merit extension of the export obligation for a period not exceeding three months. In such cases, the Regional Advance	Sub-para 23(2)	(4)

Licensing Committees may consider further extension up to six months. In the case of other exporters requests for extension in the export obligation period can be considered only by Regional Advance Licensing Committees up to a period of six months. Normally, no further extension of export obligation would be granted beyond this period. However, in exceptional cases, the Advance Licensing Committee in the Office of CCI&E, New Delhi may consider grant of further extension in the export obligation period, on the merits of each such case. In the case of export project cassettes (Audio or Video), no extension of export obligation will be granted under any circumstances by any authority."

3. The above amendments have been made in Public Interest.

R.L. MISRA,
Chief Controller of Imports & Exports
MANJULA SUBRAMANIAM, Joint Chief Controller
of Imports & Exports.